Investigations of jamming of policecommunication system by centratechnical team

1018. SHRI KAPIL VERMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a central technical team investigated the jamming of the police communications network thrice during the last few weeks;

(b) if so, whether the team could locate the private transmitter being allegedly operated by terrorists and

(c) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) to (c) The source of jamming of the police communications network has been located. Steps have been taken to remedy the situation. It is not in the public interest to disclose further details.

Replantation of forests

1019. SHRI P.N. SUKUL: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that as compared to the continuing denudation of forests, the actual replantation of trees , does not come up even upto thirty percent;

(b) if so, what are the reasons for this inadequacy in replantation; and

(c) the manner in which Government propose to meet the short fall in replantation of trees during the last ten years and by when?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI Z. R. ANSARI): (a) As per estimates of the National Remote Sensing Agency, the average annual loss of forest cover between the years 1972—75 and 1980—82 was of the order of 1.3 million hectare. The avarage annual Afforestation in the 8 year period 1974-75 to 1981-82 has been 0.4 million hectare per year. This works out to 30.7 per cent.

(b) The bottlenecks have been (1) Paucity of funds, (2) Inadequate infrastructure, (3) lack of coordination between various Social Forestry Schemes, (4) kegal and administrative constraints in motivating rural poor to take up tree planting, (5) lack of effective voluntary agencies and non-Government organisations and other decentralised structures for promoting people's involvement in the programme and (6) lack of promotional activity by Banks for Social Forestry activities.

(c) An Action Plan based on the decisions of the National Land Use and Wastelands Development Council (February 1986) has been formulated with the ultimate objective of bringing 5 million hectares per annum under Afforestation. The annual target is expected to be achieved around the close of the Seventh Five Year Plan.

मंत्रालयों में राजभाषा का प्रयोग

1020. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री सचिवालय अथवा योजना आयोग में ही अंग्रेजी के स्थान पर राजभाषा के प्रयोग को चरणबद्ध ढंग से लागू करने की सरकार की कोई योजना नहीं है ;

(ख) क्या यह सच है कि इसी कारण से वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा शिक्षा विभाग में इसका कोई कक्ष नहीं खोला गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि "क" एवं "ख" क्षेत्र को केन्द्र से सभी कार्य अंग्रेजी में ही कराना पड़ता है अन्यथा अनुवाद के नाम पर सभी कार्यों में विलम्ब होगा ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि किसी भी मंत्रालय में हिन्दी के टंकण यंत्र, टंकक तथा आशुलिपिकों की संख्या अंग्रेजी के टंकक यंत्रों, टंकण तथा आशुलिपिकों और टेलीप्रिंटरों टेलेक्स तथा कम्प्यूटरों आदि की तुलना में नगण्य है जो कि किसी भी भाषा के विकास के लिये आवश्यक हैं और राजभाषा के विकास के लिये उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमन् भारत सरकार की राजभाषा नीति सभी मंत्रालयों और केन्द्र सरकार के विभागों पर लागू है। नीति के कार्यान्वन पर नजर रखने के लिए प्रत्येक विभाग में एक हिन्दी कार्यान्वयन कक्ष/एकक हैं।

(ग) जी नहीं, श्रीमन्। भारत सरकार राज्य सरकारों को केन्द्र के साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने के लिए प्रोत्साहित करती है क्योंकि यह संघ की राजभाषा है।

(घ) प्रत्येक मंत्रालय के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार हिन्दी और द्विभाषिक टाइपराइटर प्राप्त करने आवश्यक हैं ताकि सरकार की राजभाषा नीति का उचित ढंग से कार्यान्वयन किया जा सके।

रक्षा मन्त्रालय में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग

1021. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा मंत्रालय, उत्पादन विभाग, शिक्षण तथा प्रशिक्षण संस्थानों तथा अन्य अनेक संस्थानों में राजभाषा अधिनियम, 1963 के बनने के 23 वर्ष बाद तथा 18 वर्षों से वार्षिक प्रगामी कार्यक्रम के आरम्भ किए जाने के बावजूद भी लगभग सारा कार्य अंग्रेजी में ही हो रहा है। उनकी पाठ्य पुस्तकें अंग्रेजी में हैं तथा परीक्षाएं भी अंग्रेजी में ही ली जाती हैं यदि हां, तो उसके क्या कारण है;

(ख) मंत्रालय के कौन-कौन से अनुभागों में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है यदि ऐसा कोई अनुभाग नहीं है तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि मंत्रीगण, सचिवगण एवं अन्य अधिकारी अपने सरकारी कार्य में राजभाषा का प्रयोग बिलकुल भी नहीं करते हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में रक्षा उत्पादन और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज पाटिल) : (क) से (ग) रक्षा उत्पादन तथा पूर्ति विभाग सहित रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न प्रशिक्षण स्थापनाओं, कार्यालयों आदि द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण और उनके द्वारा आयोजित परीक्षाओं में हिन्दी का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग अपना कार्य हिन्दी में करते हैं जबकि अन्य अनुभाग आंशिक रूप से हिन्दी का प्रयोग करते है। हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान रखने वाले सभी वरिष्ठ अधिकारी अपना कुछ कार्य हिन्दी में करते हैं।

Special status for Meghalaya

1022. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

whether it is a fact that the Meghalaya Chief Minister has demanded special status for Meghalaya and other hill areas as are being enjoyed by the Nagaland and Jammu and Kashmir to maintain population structure and protect ethnic culture; and

if so, the reaction of the Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI): (a) No such demand has been received from the State Government.

(b) Does not arise.

1023. *[Transferred to the* 21st *November,* 1986.].